

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण के समक्ष चुनौतियाँ

गरिमा यादव¹, अनुराधा सिंह²

¹ राजनीति विज्ञान विभाग, सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

² असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में देशों के मध्य आपस में पारस्परिक सहयोग के माध्यम से विकास हेतु क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की गई है, जैसे— यूरोप में यूरोपीय संघ, अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन, दक्षिण-पूर्व एशिया में आसियान की स्थापना हुई है, ठीक उसी तरह दक्षिण एशिया में दक्षेस की स्थापना हुई है। जिनका प्राथमिक उद्देश्य सदस्य देशों के आपसी सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाना है। अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में क्षेत्रीय संगठनों के योगदान के मामले में सार्क (5%) तुलनात्मक रूप से यूरोपियन यूनियन (55%) और आसियान (27%) के मुकाबले उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित नहीं कर रहा है, अतः इस शोध-पत्र के माध्यम से दक्षिण एशियाई एकीकरण के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान करने का प्रयास किया गया है, ताकि उन बाधाओं को दूर करके इस पूरे क्षेत्र को और उनके बीच सहयोग को गतिशील बनाया जा सके।

मूलशब्द: क्षेत्रीय एकीकरण, क्षेत्रीय संगठन, दक्षेस, दक्षिण एशिया, क्षेत्रवाद।

वैश्विक भू-राजनीति में क्षेत्रीय एकीकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें सहयोग, आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के देश एक साथ आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्षेत्रीय एकीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा पड़ोसी देश या राज्य अपनी अर्थव्यवस्थाओं, राजनीति और समाजों के स्तर पर विभिन्न पहलुओं में सहयोग और एकीकरण को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संगठन या गठबंधन बनाने के लिए एकजुट होते हैं।¹ दुनिया भर के क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता के कारण यह अवधारणा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

क्षेत्रीय एकीकरण का प्राथमिक लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत प्रायः व्यापार बाधाओं को दूर करना, आम बाजारों (कामन मार्केट) की स्थापना और एक आम मुद्रा (कॉमन करेंसी) को अपनाना शामिल होता है, जैसा कि यूरोपीय संघ में यूरो के संदर्भ में देखा गया है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय एकीकरण से व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है, जिससे सभी सदस्य देश लाभान्वित होते हैं। व्यापार बाधाओं में कमी से विशेषज्ञता और दक्षता को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है।² इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय एकीकरण राजनीतिक सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देता है। सदस्य देश अक्सर शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्षों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान दे सकता है। एक साथ काम करके, देश अंतरराष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद और पर्यावरणीय मुद्दों जैसी आम चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन अफ्रीकी संघ और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) जैसे क्षेत्रीय संगठन इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण का सटीक उदाहरण हैं।

सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण क्षेत्रीय एकीकरण का दूसरा पहलू है। लोगों के बीच बढ़ते संपर्क, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से, सदस्य राज्य आपसी समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे क्षेत्रीय सद्भाव में योगदान करते हुए सांस्कृतिक विभाजन को पाटने और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है।³

हालाँकि, क्षेत्रीय एकीकरण ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम होते हुए भी चुनौतियों से रहित नहीं है। इसमें भी अनेक प्रकार की संप्रभुता संबंधी चिंताएँ, सदस्य देशों के बीच आर्थिक असमानताएँ और राजनीतिक असहमतियाँ प्रगति में बाधा बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय एकीकरण की सफलता सदस्य देशों की साथ मिलकर काम करने और इन बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करती है। निष्कर्षतः, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीय एकीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसका उद्देश्य पड़ोसी राज्यों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना है। इसमें आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने की क्षमता है, लेकिन इसकी सफलता के लिए विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने की आवश्यकता है। बहरहाल, जैसे-जैसे दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही है, क्षेत्रीय एकीकरण संभवतः अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

दक्षिण एशिया

दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जो संस्कृति, भाषा और आर्थिक विकास के मामले में अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। दक्षिण एशिया में प्राथमिक क्षेत्रीय संगठन 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ' (SAARC) है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। SAARC में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान सहित आठ सदस्य देश शामिल हैं। अपनी क्षमता के बावजूद, सार्क को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जो सार्क क्षेत्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, 2006 में स्थापित 'दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता' (SAFTA) सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं और गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाया है।⁴ इसके अतिरिक्त, सार्क की निर्णय लेने की प्रक्रिया की अक्सर धीमी और सर्वसम्मति से संचालित होने के लिए आलोचना की जाती है, जिससे क्षेत्र में पर्याप्त एकीकरण हासिल करना मुश्किल हो जाता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सार्क ने स्वास्थ्य और शिक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में कुछ प्रगति की है, भले ही धीमी गति से।

क्षेत्रीय एकीकरण का दक्षिण एशियाई अनुभव बहुत संतोषजनक नहीं रहा है, इस क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनका प्रभावी

समाधान न होने के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग बाधित हुआ है। इस लेख में उन्हीं प्रमुख बाधाओं की पहचान करने का प्रयास किया गया है, जो कि निम्नलिखित है—

1. हथियारों की होड़— सार्क क्षेत्र के देश हथियारों पर बहुत अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में बहुत कम। दुनिया में हथियार आयातक के मामले में भारत पहले और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। तुलनात्मक दृष्टि से केवल भारत और पाकिस्तान ने वैश्विक हथियार बाजार से सऊदी अरब की तुलना में दोगुने हथियार खरीदे, जो 25 गुना अधिक अमीर है। जबकि पूरी दुनिया 1987 से प्रति वर्ष औसतन चार प्रतिशत की दर से सैन्य व्यय में कटौती कर रही है, लेकिन केवल दो क्षेत्र अफ्रीका और दक्षिण एशिया ही अपने सैन्य व्यय में वृद्धि कर रहे हैं।⁵ इससे साफ पता चलता है कि, सार्क क्षेत्र के देश आर्थिक संकट के बावजूद भी हथियारों पर बहुत अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में बहुत कम।

2. सीमापार आतंकवाद— आतंकवाद और इसके राजनीतिक परिणाम दक्षिण एशिया में अंतरराज्यीय संबंधों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। खासकर तब जब बल राज्य की नीति का एक उपकरण बन गया है और परिणामी आतंकवादी हिंसा को तर्कसंगत बना दिया गया है। इस तरह के आतंकवाद ने अंतर-राज्य संबंधों को खराब कर दिया है और पड़ोसी संबंधों में प्रवाह और तनाव पैदा कर दिया है। सार्क के सभी सदस्य देश एक-दूसरे पर इन आतंकी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगा रहे हैं,⁶ जैसे एक दशक से अधिक समय से, पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है, जैसे मुंबई ट्रेन विस्फोट, संसद हमला, ताज होटल पर हमला, उरी हमला, आदि और अन्य पड़ोसी देशों में हमले, जिसका मुख्य कारण जम्मू और कश्मीर के विवादित हिमालयी क्षेत्र में भारतीय शासन का विरोध करने वाले आतंकवादियों को समर्थन देना है।

3. बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स (इंडो-फोबिया)— भारत का दक्षिण एशिया के कुल क्षेत्रफल का 76% क्षेत्र है। इसकी जनसंख्या दक्षिण एशिया की कुल जनसंख्या का 77%⁷ है और इसका सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्र का 71% है। दक्षिण एशिया के छोटे राज्यों में इंडोफोबिया के व्याप्त होने का कारण राजनीतिक, जनसांख्यिकीय, जातीय, आर्थिक, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक कारक हैं जिन्होंने पिछले कुछ दशकों के दौरान उनके विकास और अस्तित्व को प्रभावित किया है।

4. अवैध व्यापार,— दक्षिण एशियाई क्षेत्र के राज्य अभी भी अपनी वास्तविक सामूहिक व्यापार क्षमता तक पहुँचने से बहुत दूर हैं। कुछ निरीक्षणों और टिप्पणियों के अनुसार, अवैध सीमा-पार व्यापार, जो शायद कानूनी सीमा-पार व्यापार से अधिक है, मुख्य महत्वपूर्ण कारक है जो दक्षिण एशिया को अपनी पूर्ण व्यापार क्षमता प्राप्त करने से रोकता है। आयात में वृद्धि तभी होगी जब उपभोक्ता वस्तुएँ बाजार में कम उपलब्ध होंगी। यदि माल को कानूनी रूप से आयात या निर्यात करने की कोई कानूनी व्यापार व्यवस्था नहीं है, तो अंततः अवैध आयात, निर्यात में वृद्धि होगी।⁸ नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अनौपचारिक व्यापार 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जो इस क्षेत्र में औपचारिक व्यापार से अधिक है। पाकिस्तान के साथ भारत का अनौपचारिक व्यापार समझौता औपचारिक व्यापार का लगभग दस गुना है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश के साथ अनौपचारिक व्यापार औपचारिक व्यापार के बराबर है और श्रीलंका के साथ इसका अनौपचारिक व्यापार औपचारिक व्यापार का लगभग 1/3 है। भारत और पाकिस्तान के बीच यूएसएस 2

बिलियन के अनौपचारिक व्यापार में से लगभग आधा व्यापार दुबई, मध्य एशिया जैसे तीसरे देशों के माध्यम से होता है, जबकि शेष सीमा पार अनौपचारिक व्यापार के माध्यम से होता है।⁹

5. पश्चिमी देशों पर निर्भरता— दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण से, क्षेत्रीय मामलों में पश्चिमी शक्तियों की भागीदारी सकारात्मक से अधिक नकारात्मक है।¹⁰ यह भागीदारी केवल उन पर निर्भरता के कारण है। इसका मुख्य कारण सार्क देशों का औद्योगिक पिछड़ापन और तकनीकी निर्भरता, सशस्त्र, वित्तीय निर्भरता, व्यापार आदि है।¹¹ वैश्विक प्रणाली में अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने के प्रयास में प्रमुख शक्तियों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की। इसके प्रभाव ने अन्य कारकों के साथ-साथ इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण अभिनेताओं के बीच सहयोग की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।¹² उत्पीड़न की पश्चिमी अवधारणा शेष विश्व की पश्चिम पर बौद्धिक निर्भरता को बढ़ाती है, यह उपदेश देते हुए कि पश्चिम के लिए अच्छा है बाकी के लिए भी अच्छा है। दूसरी ओर, पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना कठिन बना रहा है।

6. आपसी संदेह— सार्क के सभी सदस्य देश हर कदम पर संदेह करते हैं, सार्क के हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच विश्वास की कमी है, जिसका मुख्य कारण उनके राष्ट्रवादी हित, भावनाएँ और द्विपक्षीय संघर्ष हैं। ऐसे संघर्षों की उपस्थिति में, इस क्षेत्रीय संगठन को स्थिर स्तर पर सुसज्जित नहीं किया जा सकता है। यदि भारत किसी अन्य राज्य के साथ अपना संबंध या सहयोग विकसित करता है, तो सार्क के अन्य सभी राज्य इसे नकारात्मक रूप से लेते हैं, उसी प्रकार भारत भी। पाकिस्तान द्वारा अपने आकार और आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक और परिष्कृत हथियारों की असंगत खरीद ने भारतीय निर्णय निर्माताओं के मन में पाकिस्तान के इरादों के बारे में संदेह पैदा कर दिया है। भारत को संदेह है कि पाकिस्तान के हथियार जमावड़े और उसके बदलते रवैये के पीछे भारत को एक सीमित युद्ध में शामिल करने की इच्छा है, इसलिए पाकिस्तान के साथ अपनी सैन्य समानता बहाल करने के लिए भारत ने भी हथियार जमावड़ा शुरू कर दिया है। जिससे न केवल सहयोग के विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई, बल्कि सदस्यों के बीच एक बड़ा अंतर भी पैदा हुआ और सार्क के बेहतर परिणाम देने में विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ।

7. अंतर-राज्यीय संघर्ष— सार्क हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच सहयोग के रास्ते में अंतर-राज्य संघर्ष प्रमुख बाधाएँ हैं। इस संघ के सभी हस्ताक्षरकर्ता पड़ोसी देशों से राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय अस्थिरता महसूस करते हैं।¹³ अधिकांश सदस्य एक दूसरे के विपरीत हैं। सहयोग और बातचीत के किसी भी कार्य को लगभग सभी सदस्य संदेह की दृष्टि से देखते हैं। विश्वास की कमी की इस दृष्टि से भारत के मुख्य स्थान को किसी को नहीं भूलना चाहिए। भारत वस्तुतः और अन्यथा दक्षिण एशिया में है।¹⁴ दुनिया के किसी भी अन्य क्षेत्रीय ब्लॉक की तुलना में दक्षिण एशिया अंतर-राज्य संघर्षों के मामले में एक अनोखी तरकीब पेश करता है। भारत-बांग्लादेश विवाद, भारत-नेपाल विवाद, भारत-पाक विवाद और भारत-श्रीलंका के बीच विवाद ये सभी द्विपक्षीय विवाद क्षेत्र में प्रभावी सहयोग के रास्ते में बाधक हैं।¹⁵

8. अंतः राज्यीय संघर्ष— अंतःराज्यीय संघर्षों की समस्या सार्क को और अधिक नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि सदस्य देश अलगाववादी और विद्रोही ताकतों से बचने और भड़काने के लिए

एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं।¹⁶ दक्षिण एशिया में अंतःराष्ट्रीय संबंध अविश्वास, आपसी जोखिम धारणा, टकराव और शत्रुता के कारण विकृत हो गए हैं। राज्यों के बीच सुरक्षा में बदलाव को धमकियों के रूप में मजबूर किया जाता है; क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को पड़ोसियों से पैदा हुआ माना जाता है। इतिहास के मकड़जाल में नागरिक भी फंस गए हैं। वे अभी भी एक बड़ी इकाई से नई राष्ट्रीय इकाई बनने के दर्दनाक संक्रमण और सांप्रदायिक त्रासदियों के शिकार हैं।

भारत में कुछ समस्याएँ होना एक नियमित घटना बन गई है, जैसे सांप्रदायिक दंगे, नक्सली समस्या, रामजन्मभूमि और आजादी के बाद से भारत को जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।¹⁷ जम्मू-कश्मीर से अलग होने की आवाज और अलगाववादियों की ताकत का उदय भारत के अंदर बहुत सारी समस्या और अशांति पैदा करता है, यही कारण है कि भारत सार्क के भीतर सहयोग में आपसी क्षेत्रीय विकास और प्रगति हेतु अपना 100: देने में असमर्थ है। सीमा के दूसरी ओर, पाकिस्तान अपने जन्म के बाद से ही किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहा है, पहले तो देश हमेशा एक चुनी हुई सरकार के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन अधिकांश बार उसे सफलता नहीं मिल पाई, इसलिए उसके बाद से देश पर अधिकतम बार सेना का शासन रहा। जिसने कई कट्टरपंथी समूहों को प्रोत्साहित किया, जिन्होंने न केवल देश में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में बहुत खतरा पैदा कर दिया। पिछले दशक से एक और समस्या जिसने पाकिस्तान को क्षेत्रीय प्रगति से दूर रखा है वह है सुनी और शिया संघर्ष, ये संप्रदाय हमेशा एक-दूसरे पर हमला करते हैं जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारे लोग हताहत होते हैं। यही कारण है जो पाकिस्तान को सार्क जैसे क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान देने में बाधा डालते हैं। श्रीलंका आंतरिक अशांति से पीड़ित दूसरा राज्य है जो गृहयुद्ध के स्तर तक पहुंच गया है। श्रीलंका में तमिल अलगाववादी आंदोलन की जड़ें 19वीं सदी में थीं। हाल ही में सार्क में शामिल हुए देश अफगानिस्तान को भी पिछले दशक से कई आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे आर्थिक और आतंकवाद के लिए संघर्ष करना आदि। ये समस्याएँ देश को अपनी समस्याओं में व्यस्त रखती हैं और इसे क्षेत्रीय विकास से दूर रखती हैं। परिणामस्वरूप, वे अभी तक अपने ही देशों में क्षेत्रीय सहयोग के लिए पर्याप्त मांग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। हालाँकि, विभिन्न सार्क देशों के प्रबुद्ध नागरिकों के विभिन्न समूहों के बीच कई आदान-प्रदान हुए हैं, जिससे एक शांतिपूर्ण दक्षिण एशियाई समुदाय के विकास की कुछ आशा दिखाई देती है। लेकिन इन समूहों द्वारा जगायी गयी उच्च उम्मीदें अभी भी पूरी होनी बाकी हैं। दरअसल, ये उम्मीदें समय-समय पर होने वाले आतंकवादी और सांप्रदायिक हमलों से टूट सकती हैं।

9. सीमित अंतर्क्षेत्रीय व्यापार— दक्षिण एशियाई देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय निवेश और व्यापार बहुत कम है और वर्षों से स्थिर बना हुआ है। इन देशों के बीच परस्पर निर्भरता काफी सीमित है। दक्षिण एशियाई अंतर-क्षेत्रीय व्यापार दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। कुछ अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में यह प्रति वर्ष लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।¹⁸

10. पिछड़ी अर्थव्यवस्था और खराब बुनियादी ढांचा— क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण के विकास में खराब बुनियादी ढांचा मुख्य बाधाओं में से एक है। खराब बुनियादी ढांचा अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के उच्चतम स्तर को न्यूनतम कर देता है। सड़क या बंदरगाह की भीड़ और सीमा शुल्क के कारण पारगमन में देरी से निर्यातकों के लिए लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा, दक्षिण एशिया के देशों में कुछ बुनियादी आर्थिक समानताएँ शामिल हैं

जैसे उद्योगों में पुरानी तकनीक, कम आय, आकर्षक श्रमिक और तुलनात्मक लाभ जैसे चाय, तैयार कपड़े और अन्य वस्तुएँ। ये सामान्य विशेषताएँ अक्सर सापेक्ष लाभदायक लाभों से प्रेरित अंतर-क्षेत्रीय व्यापार की संभावनाओं को कम कर देती हैं।¹⁹

11. कठिन व्यावसायिक वातावरण— व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार संबंधी जानकारी जैसे उत्पाद की जरूरतें, प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता, ज्ञान, मूल्य, टैरिफ, औद्योगिक रुझान, व्यावसायिक नियम और प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं। हालाँकि, सार्क देशों ने सार्क देशों के बीच वाणिज्यिक सूचनाओं के सुचारु आदान-प्रदान की सुविधा के लिए कोई मजबूत तंत्र नहीं अपनाया है। इसी तरह, पारगमन में माल की स्थिति का पता लगाना और सर्वोत्तम गुणवत्ता का चयन करना और उन्हें आधिकारिक तौर पर चुनना, पारंपरिक व्यापारों में भी पारगमन में महत्वपूर्ण है, जिसमें बार-बार सीमा पार व्यापार का मूल्य अधिक होता है। व्यापार भागीदार कीमतों को कम करने के लिए तथा सभी आवश्यक सहायता पाने हेतु अनौपचारिक व्यापार में शामिल होते हैं; इसलिए, कम लेन-देन की लागत, अनौपचारिक चैनलों में व्यापार ने व्यापारियों को सीमा पार व्यापार में इस विशेष स्ट्रीम का चयन करने के लिए मजबूर किया है। सार्क क्षेत्र के देशों के भीतर उचित बहुउद्देश्यीय पारगमन व्यवस्था की अनुपस्थिति क्षेत्र के भीतर अनौपचारिक सीमा को बढ़ाने में एक और महत्वपूर्ण कारक है। सार्क देशों के भीतर औद्योगिक असमानता एक और कारण है जो सार्क देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय औपचारिक व्यापार के विकास को कम करती है जो अंततः अनौपचारिक व्यापार के विकास का कारण बनती है।²⁰

12. कमजोर संस्थागत ढांचा और अक्षम सरकारी ताकत— एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो पिछले दशकों से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की धीमी वृद्धि का कारण बना, वह दक्षिण एशियाई सरकारों की कमजोर ताकत थी। व्यापक जन समर्थन और सामाजिक आधार की कमी के कारण कमजोर सरकारों में नेताओं के लिए प्रमुख घरेलू अभिनेताओं के समर्थन के बिना घरेलू और विदेशी नीतियों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाना, बनाना मुश्किल हो जाता है।

पिछले दशकों से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की धीमी वृद्धि का कारण दक्षिण एशियाई देशों के बीच संचार में पारदर्शिता की कमी भी थी। दक्षिण एशिया में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही अत्यधिक सरकारी विनियमित हैं, जिससे सूचना प्रवाह विकृत और विलंबित होता है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियाँ नियमित आधार पर एक-दूसरे के खिलाफ व्यवस्थित दुष्प्रचार अभियान चलाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके पड़ोसियों की नीतिगत प्राथमिकताओं और घरेलू स्थितियों के बारे में सटीक और समय पर जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। घरेलू पारदर्शिता और संचार के निहित पैटर्न की कमी के क्षेत्रीय सहयोग पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।

13. उत्पत्ति और गंतव्य के प्रतिबंधात्मक नियम— प्रतिबंधात्मक नियमों से अवैध व्यापार और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है।

अ. टैरिफ बाधाएँ— सार्क क्षेत्र के भीतर, उच्च टैरिफ अवैध व्यापार को प्रोत्साहित करता है। उच्च टैरिफ दरें टैरिफ से बचने के लिए कानूनी चैनलों से बचने के लिए एक मजबूत चिंता पैदा करती हैं। यह देखा जा सकता है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बुनियादी और निर्मित दोनों वस्तुओं पर टैरिफ अधिक हैं। गैरकानूनी, विनिर्मित वस्तुएँ भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में अधिक हैं। गैरकानूनी चैनल बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष रूप से आकर्षक है, जिसे भारत से अन्य

दक्षिण एशियाई देशों में अवैध रूप से निर्यात किया जा रहा है। ऐसे उत्पाद बड़ी कंपनियों द्वारा विकसित नहीं किए जा रहे हैं। टैरिफ ऐसे संस्थानों के लिए अंतिम कीमत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है और उन्हें अवैध व्यापार लाभ देता है।²¹

ब. गैर टैरिफ बाधाएँ— अंतर-सार्क व्यापार का अंत केवल उच्च टैरिफ के कारण नहीं है, बल्कि गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) की उपस्थिति के कारण भी है, ज्यादातर मात्रा प्रतिबंध इस तरह की बाधाओं से क्षेत्र में अवैध व्यापार में वृद्धि होती है। 1990 की शुरुआत में, भारत और बांग्लादेश ने प्राथमिक और तैयार उपकरणों दोनों के लिए सबसे गैर-टैरिफ बाधाओं के कवरेज को समानुपातिक बना दिया है। वास्तव में, भारत में बुनियादी उपकरणों पर एनटीबी कवरेज अनुपात 72 प्रतिशत और निर्मित पर 59 प्रतिशत अनुपात था। बांग्लादेश अनुपात और आनुपातिक रूप से 55% और 47% के एनटीबी का अनुपात विकसित किया।²²

इन सब के परिणामस्वरूप अवैध व्यापार का वित्तपोषण होता है, अवैध बाजार बनता है जिसमें भारी मात्रा में काला धन होता है, जिसे व्यापारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह पैसा अवैध मुद्रा बाजार के माध्यम से दुनिया के किसी भी देश में स्थानांतरित किया जा सकता है। घरेलू और विदेशी मुद्रा दोनों से युक्त एक बड़ी काली अर्थव्यवस्था ऐसे व्यापार को संभव बनाती है। अनधिकृत व्यापार को सोने या चांदी जैसी उच्च लागत वाली कीमती धातुओं या अवैध धन नेटवर्क से तरल धन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। पहले मामले में, सोने की भौतिक रूप से तस्करी की जाती है और फिर उसे वांछित मुद्रा में बदल दिया जाता है। इस प्रणाली की विशिष्टता यह है कि इसमें कोई भौतिक धन हस्तांतरण नहीं होता है। इस तंत्र को भारत में ष्वालाष् कहा जाता है, बांग्लादेश में शहुंडीश् और श्रीलंका में शिचटश् फंड इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है।²³

14. आवश्यकताओं की जानकारी का अभाव— सार्क देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के रास्ते में एक और बढ़ती बाधा उनकी जरूरतों, धारणाओं और संवेदनशीलता के संदर्भ में एक दूसरे देश के बारे में बेहद कम जानकारी है। भौतिक निकटता के बावजूद, दक्षिण एशिया में नीति निर्माता एक-दूसरे से बहुत अलग रहे हैं और उन्होंने विकसित देशों के साथ संबंधों पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। इस अज्ञानता के कारण रुचि और चिंता की कमी हो गई है। इसलिए, रचनात्मक बातचीत और संचार क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में एक प्रमुख तत्व हैं। जिन क्षेत्रों में सहयोग पहले से ही हो रहा है, उनकी पहचान करके और बढ़ाने की जरूरत है और जिन क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग संभव है, उनकी मौजूदा बाधाओं को दूर करके उसे अस्तित्व में लाना चाहिए।

15. कमजोर परिवहन और बुनियादी ढांचा— क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण के विकास में खराब बुनियादी ढांचा मुख्य बाधाओं में से एक है।²⁴ खराब बुनियादी ढांचा अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के उच्चतम स्तर को न्यूनतम कर देता है। सड़क या बंदरगाह की भीड़ और सीमा शुल्क के कारण पारगमन में देशी से निर्यातकों के लिए लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा, दक्षिण एशिया के देशों में कुछ बुनियादी आर्थिक समानताएँ शामिल हैं जैसे उद्योगों में पुरानी तकनीक, कम आय, आकर्षक श्रमिक और तुलनात्मक लाभ जैसे चाय, तैयार कपड़े और अन्य वस्तुएँ। ये सामान्य विशेषताएँ अक्सर सापेक्ष लाभदायक लाभों से प्रेरित अंतर-क्षेत्रीय व्यापार की संभावनाओं को कम कर देती हैं। वार्षिक आय का निचला स्तर भी अंतर्राष्ट्रीय उद्योग की क्षमता तक ही सीमित है।²⁵ एक अनुमान से पता चलता है कि यदि दक्षिण एशियाई बुनियादी ढांचे में वृद्धि हुई है, पूर्वी एशिया के स्तर तक आधा, तो अंतर-क्षेत्रीय

व्यापार में 60% की वृद्धि होगी।²⁶ दक्षिण एशियाई देशों के उद्योग निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करते हैं जिससे बाजार का आकर्षण कम हो जाता है, खराब गुणवत्ता का मुख्य कारण उद्योगों में पुरानी तकनीक का उपयोग है। सार्क देश आज भी तकनीक के मामले में पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं। यह दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली एक बड़ी बाधा बन गई।²⁷ सर्वेक्षणों ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खराब बुनियादी ढांचे को एक विशेष समस्या के रूप में पहचाना है। परिवहन अवसंरचना और सेवाओं के सभी तरीकों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सड़कों की खराब स्थिति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क के बीच अंतर-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की कमी, अविश्वसनीय और कुल मिलाकर महंगी सड़क परिवहन सेवाएँ, भीतरी इलाकों और अन्य के साथ बंदरगाहों की अपर्याप्त सड़क और रेल संपर्क। इससे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई और सार्क क्षेत्र के लाखों लोगों को बुनियादी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं तक पहुंच नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पहुंच आर्थिक मुख्यधारा से अलगाव की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे क्षेत्र की बड़ी ग्रामीण आबादी में गरीबी की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।²⁸

16. गरीबी— विश्व अर्थव्यवस्था में दक्षिण एशिया की समग्र स्थिति इसके आकार और जनसंख्या के अनुपात में निराशाजनक और असंगत है। दक्षिण एशिया, जिसमें दुनिया की आबादी का 20% और दुनिया की भूमि की सतह का 2.7% शामिल है, 1987 में दुनिया के कुल निर्यात और आयात व्यापार में निर्यात का मात्र 0.81% और आयात का 1.31% हिस्सा था। संगठन के आठ देश बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल और अब अफगानिस्तान सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में सूचीबद्ध हैं।²⁹ यह क्षेत्र अफ्रीका के बाद दूसरा सबसे गरीब क्षेत्र है।

दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक उन पर विदेशी ऋण का लगातार बढ़ता बोझ रहा है। सामान्य रूप से विकासशील देशों की बाह्य ऋण की समस्या और विशेष रूप से सार्क देश, उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों के साथ एकीकृत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे विकासशील देशों की संप्रभुता और अखंडता खत्म होने का डर बढ़ जाता है।

निष्कर्ष

आसियान और ईयू की तरह ही क्षेत्रीय सहयोग से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, परंतु दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग में हमने उपरोक्त अनेक चुनौतियों को जाना है, जो सार्क के प्रदर्शन को सीमित कर रहा है, यदि दक्षिण एशियाई राज्य विशेषकर भारत-पाकिस्तान अपने संबंधों को सुधार कर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बुनियादी ढांचे के विकास में साथ मिल कर सहयोग करे व व्यापार बाधाएँ दूर करने का प्रयास करें और यदि मजबूत सक्षम नेतृत्व मिले तो दक्षिण एशिया अपनी इन चुनौतियों का सामना कर सकता है, इससे सदस्य देशों में सहयोग बढ़ेगा और आम जनता भी लाभान्वित होगी, व्यापारिक सहयोग बढ़ने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी।

संदर्भ सूची

1. एडवर्ड मैसफील्ड – एटेल सोलिड्गन, "रीजनलिज्म", ऐन्थूअल रीव्यूज ऑफ पोलिटिकल साइंस, 2010 www.annualreviews.org 11 january, 2024 को एक्सेस किया गया।
2. एडवर्ड मैसफील्ड, 2010

3. उत्तरा सहस्रबुद्धे, "थ्योरीज ऑफ रीजनलिज़्म इन साउथ एशिया", मोहनान बी. पिल्लई, ए. एस. राजू (सं), "कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेसन इन साउथ एशिया", कलपाज पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2015, पेज नं. 5
4. उत्तरा सहस्रबुद्धे, पेज नं. 6
5. मोहन इन्द्र झा, "सार्क; द रोड अहेड", राष्ट्रीय पुस्तक संगठन, नई दिल्ली, 2004, पेज नं. 79
6. आनंद कुमार, "द टेरर चौलेंज इन साउथ एशिया एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली, 2012, पेज नं. 1
7. वी. आई. अरोरा, "सार्क प्रोस्पेक्ट्स एंड कोऑपरेशन", इंडिया क्वार्टरली, न्यू दिल्ली, वॉल. 42, जनवरी- मार्च 1986, पेज नं. 69
8. आर. एस. खेर, "सार्क पॉलिटिकल एंड एकोनॉमिक आस्पेक्ट्स", डोमीनेंट पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, 2004, पेज नं. 196-200
9. इसाबेल "द कोस्टा, "द सेकंड फ्रीडम साउथ एशियन चौलेंजेस 2005-2025, स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ग्रुप, मुंबई, 2005, पेज नं. 12
10. एम.एच. सईद, "सार्क चलेंजेज अहेड", 2003, पेज नं 97
11. ई. सुधाकर, "सार्क, ओरिजिन, ग्रोथ एंड फ्यूचर", ज्ञान पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1994, पेज नं. 80
12. ई. सुधाकर, पेज नं. 128-129
13. शाहीन इरुम, "साउथ एशियन असोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (सार्क)", e-issn जर्नल, वॉल. 15, इशू 6, म-पेद 2279-0837, सितंबर-ऑक्टूबर 2013, पेज नं. 4
14. अहमद रजा खान, "इंफेडिमेंट्स टू द सक्सेस ऑफ सार्क", अरिस्चर्च जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडीस, वॉल. 30, नं 1, जनवरी-जून 2015, पेज नं. 296
15. डॉ महाराज हजनी, "व्हाई सार्क हैज फेल्ड", न्यूज पेपर, ग्रेटर कश्मीर, 10 मई, 2007
16. के. मुखर्जी, "द साउथ एशियन असोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन : प्रॉब्लेम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स", प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट स्टडीस, 2014, 14(4), 373-381, <https://doi.org/10.1177/1464993414521524>
17. ई. सुधाकर, पेज नं. 66-67
18. इसाबेल ब्रूटो द कोस्टा, पेज नं. 10
19. ई. सुधाकर, पेज नं. 80
20. इसाबेल ब्रूटो द कोस्टा, पेज नं. 13
21. संजय कठौरीया, "अ ग्लास ऑफ फुल: द प्रामिस ऑफ रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया", वाशिंगटन, डी. सी., वर्ल्ड बैंक, 2018, पेज नं. 75
22. संजय कठौरीया, पेज नं. 76
23. निशा तनेजा, "इनफॉर्मल ट्रेड इन द सार्क रीजन", साउथ एशियन स्टडीस, नई दिल्ली, 1999, पेज नं. 18-19
24. राजीव कुमार, "सार्क चेंजिंग रियलिटीज ऑपरचुनिटीज एंड चौलेंजेस, पेज नं. 9
25. किशोर सी. दास, "रीजनलिज़्म इन साउथ एशिया", राउटलेज, न्यूयॉर्क, 2008 पेज नं. 112
26. राजीव कुमार, "सार्क चौन्जिंग रियलिटीज ओपॉरचुनिटीज एंड चौलेंजेस, पेज नं. 9
27. ई. सुधाकर। पेज नं. 80
28. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, <http://webworldbank/external/southasia/infrastructure>
29. ई. सुधाकर, पेज नं. 77-78